

प्रेषक,

मंजुल कुमार जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
हरिद्वार।

राजस्व अनुभाग-2

देहरादून: दिनांक: 23 / 12, '2008

विषय:-मै0 आर्किड कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम गदरजुड्डा, तहसील रुडकी जनपद हरिद्वार में कुल 1.4681 है0 भूमि क्रय की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके प्रस्ताव/पत्र संख्या-815/भूमि व्यवस्था दिनांक 18-09-2008 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय उक्त कम्पनी को कुल 3.7417 है0 भूमि क्रय की अनुमति से सम्बन्धित पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या-146-भू0क0/18(1)/2007 दिनांक-09अक्टूबर2007 में उल्लिखित खाता संख्या-369 में खसरा संख्या-307 एवं 308 कुल रकबा 1.4681 है0 भूमि के रथान पर मै0 आर्किड कैमिकल्स एवं फार्मास्यूटिकल्स को फार्मास्यूटिकल उद्योग की स्थापना हेतु ग्राम गदरजुड्डा, तहसील रुडकी जनपद हरिद्वार में आपके उपरोक्त पत्र के द्वारा अनुमोदित/संस्तुत खसरा संख्याओं/गाटा संख्याओं, 873म रकबा 1.3998 है0 एवं गाटा संख्या-872 रकबा 0.0683 है0 कुल रकबा 1.4681 है0 भूमि, उत्तरांचल, (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2003 दिनांक 15-1-2004 की धारा-154(4)(3)(क)(V) के अन्तर्गत कय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ प्रदान करते हैं:-

1- केंता धारा-129-ख के अधीन विशेष श्रेणी का भूमिधर बना रहेगा और ऐसा भूमिधर भविष्य में केवल राज्य सरकार या जिले के कलेक्टर, जैसी भी स्थिति हो, की अनुमति से ही भूमि कय करने के लिये अर्ह होगा।

2- केंता बैंक या वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने के लिये अपनी भूमि बन्धक या दृष्टि बन्धित कर सकेगा तथा धारा-129 के अन्तर्गत भूमिधरी अधिकारों से प्राप्त होने वाले अन्य लाभों को भी ग्रहण कर सकेगा।

3- केंता द्वारा कय की गई भूमि का उपयोग दो वर्ष की अवधि के अन्दर, जिसकी गणना भूमि के विकय विलेख के पंजीकरण की तिथि से की जायेगी अथवा उसके बाद ऐसी अवधि के अन्दर जिसको राज्य सरकार द्वारा ऐसे कारणों से जिन्हें लिखित रूप में अभिलिखित किया जायेगा।

भूमि का उपयोग उसी प्रयोजन (औद्योगिक प्रयोजन) के लिए करेगा जिसके लिये अनुज्ञा प्रदान की गई है यदि वह ऐसा नहीं करता अथवा उस भूमि का उपयोग जिसके लिये उसे स्वीकृत किया गया था, उससे भिन्न किसी अन्य प्रयोजन हेतु करता है अथवा जिस प्रयोजनार्थ कय किया गया था उससे भिन्न प्रयोजन के लिये विकय, उपहार या अन्यथा भूमि का अन्तरण करता है तो ऐसा अन्तरण उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु शून्य हो जायेगा और धारा-167 के परिणाम लागू होंगे।

4- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी अनुसूचित जाति/जनजाति के न हों और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भूमिधर होने की स्थिति में भूमि कय से पूर्व सम्बन्धित जिलाधिकारी से नियमानुसार अनुमति प्राप्त की जायेगी।

5- जिस भूमि का संक्रमण प्रस्तावित है उसके भूस्वामी असंक्रमणीय अधिकार वाले भूमिधर न हों।

6- शासन द्वारा दी गयी भू कय की अनुमति शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 180 दिनों के लिये वैध होगी।

7- स्थापित किये जाने वाले उद्योग में उत्तराखण्ड मूल के बेरोजगारों को न्यूनतम 70 प्रतिशत रोजगार उपलब्ध कराया जायेगा।

8- कय की जाने वाली भूमि का भू-उपयोग यदि औद्योगिक से भिन्न हो तो उसे नियमानुसार औद्योगिक में परिवर्तित कराकर शासन द्वारा निर्धारित नीति/मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अन्तर्गत प्रचलित नियमों/मानकों एवं भवन उपविधियों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करते हुए औद्योगिक प्रयोजन हेतु भवन निर्माण का प्लान सक्षम अधिकारी से स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

9- खसरा संख्या-872 तथा खसरा संख्या-873म भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-50/2003 दिनांक-10.06.2003 के द्वारा किसी भी श्रेणी के अन्तर्गत अधिसूचित नहीं है। भारत सरकार के नोटिफिकेशन संख्या-1/10/2001-एन0ई0आर0 दिनांक-07.01.2003 के अनुसार प्रस्तावित उद्योग का उत्पाद (फार्मा प्रोडक्ट) थ्रस्ट सेक्टर के अन्तर्गत है। इकाई को निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण करने पर केन्द्रीय औद्योगिक पैकेज का लाभ अनुमन्य होगा।

10- प्रस्तावित उद्योग का निर्माण कार्य राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (सीडा) के अन्तर्गत जी0आई0डी0सी0आर0-2005 में उल्लिखित शर्तों के अधीन होगा तथा इकाई का निर्माण कार्य सीडा रॉ ले-आउट स्वीकृत कराने के पश्चात् ही स्थल पर निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

11- प्रस्तावित स्थल पर अवस्थापना विकास से सम्बन्धित कार्यों का दायित्व सम्बन्धित इकाई का होगा। इकाई द्वारा क्रय की जाने वाली भूमि का उपयोग, फार्मा प्रोडक्ट के किया कलापों की स्थापना हेतु किया जायेगा।

12- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में रपॉट जोनिंग क्षेत्र के लिए निश्चित सिद्धान्त/नीतियों का पूर्णतः पालन किया जायेगा। इकाई में पूंजी निवेश/निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व ड्रग कन्ट्रोलर से ड्रग लाइसेंस, प्रदूषण नियंत्रण हेतु उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा अग्निशमन विभाग आदि से नियमानुसार अनापत्ति/सहमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी।

13- प्रश्नगत उद्योग की स्थापना के सम्बन्ध में अनापत्ति मात्र भूमि क्रय व्यवस्था के सन्दर्भ में दी जा रही है।

14- किसी दशा में प्रस्तावित क्रेताओं को प्रस्तावित भूमि के अतिरिक्त अन्य भूमि के उपयोग की अनुमति नहीं होगी एवं सार्वजनिक उपयोग की भूमि या अन्य कोई भूमि पर कब्जा न हो इसके लिये भूमि क्रय के तत्काल बाद उसका सीमांकन कर लिया जाय।

15- भूमि का विक्रय अपरिहार्य परिस्थितियों के अतिरिक्त अनुमन्य नहीं होगा एवं ऐसी दशा में विक्रय किये जाने हेतु सकारण शासन का अनुमोदन प्राप्त करना होगा।

16- योजना प्रारम्भ से पूर्व नियमानुसार सम्बन्धित विभागों/संस्थाओं से विधिक व अन्य अनापत्तियाँ/स्वीकृतियाँ प्राप्त कर ली जायेगी।

17- उपरोक्त शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन न होने, गिन्ना उपयोग करने, उल्लंघन होने पर अथवा किसी अन्य कारणों से, जिसे शासन उचित समझता हो, प्रश्नगत स्वीकृति निरस्त कर दी जायेगी।

कृपया इस सम्बन्ध में तदनुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(मंजुल कुमार जोशी)

अपर सचिव

संख्या एवं तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- मुख्य राजस्व आयुक्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश के उद्योग विभाग से सम्बन्धित समस्त विन्दुओं का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।